1

दृष्टि The Vision

drishti

GENERAL STUDIES (Test–2)

निर्धारित समयः तीन घंटे
Time allowed: Three Hours

DTVF/23 (J-A)–M–**GSM (P-III)-2302**

अधिकतम अंकः 250
Maximum Marks: 250

Name: Neeraj Dhakad

Mobile Number:

Medium (English/Hindi): Hindi

Reg. Number:

Center & Date: Mukherjee nagar 27/06/2023

UPSC Roll No. *(If allotted)*: 6316307

प्रश्न-पत्र के लिये विशिष्ट अनुदेश

कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें:
इसमें बीस प्रश्न हैं तथा हिन्दी और अंग्रेज़ी दोनों में छपे हैं।
सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिये गए हैं।
प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहियें जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिये। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिये।
प्रश्न-सह-उत्तर-पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिये।

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instruction carefully before attempting questions:
*There are **TWENTY** questions printed both in **HINDI** and **ENGLISH**.*
All the questions are compulsory.
The number of marks carried by a question is indicated against it.
Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.
Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.
Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

केवल मूल्यांकनकर्त्ता द्वारा भरा जाए *(To be filled by Evaluator only)*

Question Number	Marks	Question Number	Marks
1.		11.	
2.		12.	
3.		13.	
4.		14.	
5.		15.	
6.		16.	
7.		17.	
8.		18.	
9.		19.	
10.		20.	
Grand Total (सकल योग)			

मूल्यांकनकर्त्ता (हस्ताक्षर)
Evaluator (Signature)

पुनरीक्षणकर्त्ता (हस्ताक्षर)
Reviewer (Signature)

GENERAL STUDIES (Test–2)

निर्धारित समय: तीन घंटे *Time allowed: Three Hours*	DTVF/23 (J-A)–M–**GSM (P-III)-2302**	अधिकतम अंक: 250 *Maximum Marks: 250*

Name: Neeraj Dhakad **Mobile Number:** ______

Medium (English/Hindi): Hindi **Reg. Number:** ______

Center & Date: Mukherjee nagar 27/06/2023 **UPSC Roll No.** *(If allotted)*: 6316307

प्रश्न-पत्र के लिये विशिष्ट अनुदेश

कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें:

इसमें बीस प्रश्न हैं तथा हिन्दी और अंग्रेज़ी दोनों में छपे हैं।

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिये गए हैं।

प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहियें जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिये। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।

प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिये।

प्रश्न-सह-उत्तर-पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिये।

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instruction carefully before attempting questions:

*There are **TWENTY** questions printed both in **HINDI** and **ENGLISH**.*

All the questions are compulsory.

The number of marks carried by a question is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.

Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

केवल मूल्यांकनकर्त्ता द्वारा भरा जाए *(To be filled by Evaluator only)*

Question Number	Marks	Question Number	Marks
1.		11.	
2.		12.	
3.		13.	
4.		14.	
5.		15.	
6.		16.	
7.		17.	
8.		18.	
9.		19.	
10.		20.	
Grand Total (सकल योग)			

मूल्यांकनकर्त्ता (हस्ताक्षर)
Evaluator (Signature)

पुनरीक्षणकर्त्ता (हस्ताक्षर)
Reviewer (Signature)

drishti | दृष्टि The Vision

Feedback

1. Context Proficiency (संदर्भ दक्षता)
2. Introduction Proficiency (परिचय दक्षता)
3. Content Proficiency (विषय-वस्तु दक्षता)
4. Language/Flow (भाषा/प्रवाह)
5. Conclusion Proficiency (निष्कर्ष दक्षता)
6. Presentation Proficiency (प्रस्तुति दक्षता)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

1. "अध्यादेश का पुनः प्रख्यापन, संविधान के साथ एक छल तथा लोकतांत्रिक विधायी प्रक्रिया का विध्वंस है।" प्रमाणित कीजिये। (150 शब्द) 10

"Repromulgation of Ordinance is a fraud on the constitution and a subversion of democratic legislative process". Substantiate. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारतीय संविधान में शक्तियों का सकारात्मक विभाजन किया गया है, लेकिन एक ऐसी परिस्थिति जिसमें विधी निर्माण आवश्यक है कार्यपालिका अर्थात् राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश अनुच्छेद-123 के तहत लाया जाता है, ऐसी ही व्यवस्था राज्य स्तर पर राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 213 के माध्यम से लाई जाती है

अत: डी.सी. वाधवा बनाम बिहार राज्य (1987) में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अध्यादेश का बार-बार लाया जाना संविधान का उल्लंघन है और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के खिलाफ है।

वस्तुत: अध्यादेश विधि निर्माण का दायित्व कार्यपालिका को सौंपता है जबकि विधी निर्माण का अधिकार विधायिका है और यह व्यवस्था संसदीय शासन

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया के ~~[struck out]~~ विरुद्ध कार्यपालिका को महत्व प्रदान करती है।

साथ ही अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 सप्ताह की अवधि उसके बाद इसे लोकसभा और राज्यसभा से सहमति लेनी आवश्यक है तत्पश्चात ही यह 6 माह तक प्रभावी होगा।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि संविधान में विधि निर्माण का अधिकार विधायिका को दिया गया, इसलिये अध्यादेश को विधायिका समानांतर समझना उचित नहीं है, अतः इसका उपयोग अति आवश्यक समय में ही किया जाये तो संसदीय एवं लोकतांत्रिक परिपाटियों के लिये सही होगा

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

2. "मूल संरचना का सिद्धांत आवश्यक और वांछनीय दोनों है।" कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (150 शब्द) 10

"Doctrine of basic structure is both necessary and desirable." Critically analyze the statement. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

केशवानंद भारती वाद बनाम केरल राज्य (1973) में उच्चतम न्यायालय ने आधारभूत संरचना को प्रस्तुत किया, और स्पष्ट किया कि संसद जब संविधान को पुनः लिख नहीं सकती तो न्यायपालिका भी संविधान को परिवर्तित नहीं कर सकती है और इसके सिद्धांत, आदर्श एवं मूल्य आधारभूत संरचना माने जायेंगे, जिनका निर्णय करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय का है

मूल संरचना की आवश्यकता क्यों?

→ मूल अधिकारों का उल्लंघन
→ संसद का मनमानी अधिकार
→ अनुच्छेद 368 में परिवर्तन
→ विधि के शासन की अवहेलना
→ संवैधानिक प्रक्रियाओं का उल्लंघन
→ भूमि सुधार मुद्दा
→ संवैधानिक सर्वोच्चता के लिये
→ अनेक संविधान संशोधन

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

मूल संरचना से लाभ

- → विधि का शासन मजबूत अनु-14
- → संघीय शासन अनु-368
- → मूल अधिकारों के स्वतंत्रता
- → संवैधानिक सर्वोच्चता स्थापित
- → नीति निदेशक तत्वों की प्रकृति मजबूत
- → संसद का मनमानी अधिकार पर प्रतिबंध → उदाहरण - 99वें संविधान संशोधन की समाप्ति
- → संघवाद को बढ़ावा → S.R. बोम्मई वाद 1994
  - SC/ST Act के संशोधन की समाप्ति
- → जीवन के अधिकार का विस्तार → मेनका गांधी वाद-1978 → शायराबानो वाद → निजता (प्राइवेसी) के अधिकार।

निष्कर्षतः मूल संरचना के लाभों के साथ कुछ हानियां भी हुई जो लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है जैसे संसद के संवैधानिक संशोधन पर प्रतिबंध आरोपित हुआ और न्यायपालिका की सक्रियता में वृद्धि, लेकिन इन सीमाओं के बावजूद आधारभूत संरचना ने सरकार एवं विधायिका पर प्रतिबंध आरोपित किया कि वे लोगों के हितों के लिये संशोधन पर बल दें संविधान की संरचना में परिवर्तन न करें।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright - Drishti The Vision Foundation

3. भारतीय प्रवासी समुदाय की प्रासंगिकता तथा भारत के आर्थिक एवं सामरिक हितों के संवर्द्धन में इनकी भूमिका पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

Discuss the significance of India's diaspora and its role in enhancing India's economic and strategic interests. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

भारतीय प्रवासी नागरिक वह है, जो 182 दिनों से लगातार भारत के बाहर रहा हो और उद्देश्य रोजगार हो।

भारतीय प्रवासी समुदाय की प्रासंगिकता

- → प्रवासी नागरिक भारतीय विशेषताओं को विदेश में प्रसारित
- → सामाजिक-सांस्कृतिक विस्तार
  - दीवाली
  - छठ पूजा
  - होली
- → शिक्षा एवं चिकित्सा के क्षेत्र में जो संबंधों को बेहतर करता है
- → बाहर कार्य करने के पश्चात कुशल व्यक्ति के रूप में भारत में विकास
- → वैश्वीकरण के इस युग में प्रवासी समुदाय भारत का विश्व में सबसे अधिक धन प्रेषण करता है
  - 100 बिलियन डॉलर से अधिक

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright - Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

भारत के आर्थिक हितों पर प्रभाव

- आर्थिक धन की प्राप्ति — 100 बिलियन डॉलर
- रोजगार की प्राप्ति
- FDI में वृद्धि
- मसाला बॉन्ड के माध्यम से रुपी डिनोमिनेटेड धन एकत्रित करना
- वैज्ञानिक तकनीकी विकास
- औद्योगिक विकास

सैनिक
- विश्व की तीसरी सबसे बड़ी सेना
- संबंधों में बेहतरी

सामाजिक
- सामाजिक — भारतीय समाज पर प्रभाव — बॉलीवुड कहानी
- सांस्कृतिक — भारतीय त्योहारों का प्रचलन होली, दिवाली आदि
- सॉफ्ट पावर का प्रभाव

राजनीतिक
- भारत का राजनीतिक प्रभाव बढ़ा
  - अमेरिकी चुनाव प्रचार में "हाउडी मोदी" कार्यक्रम
- UNSC में स्थायी सदस्यता की मजबूत मांग में सहयोग

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

4. "राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) एक अनूठा मंच है, जिसे देश भर में पर्यावरणीय मुद्दों को स्वतः संज्ञान में लेने की शक्तियाँ प्राप्त हैं।" इस संदर्भ में राष्ट्र के पर्यावरण शासन में NGT के महत्त्व का विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द) 10

"National Green Tribunal (NGT) is a unique forum endowed with suo motu powers to take up environmental issues across the country." In this context analyse the importance of NGT for environmental governance of the nation. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत NGT का गठन हुआ एवं आस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बाद भारत ऐसा करने वाला तीसरा देश बना है मुख्यालय - नई दिल्ली में अवस्थित है।

साथ NGT को उच्च न्यायालय के समान शक्तियां दी गई है और इसके निर्णय के विरुद्ध NGT के अंतर्गत ही अपील किया जा सकता है तो साथ ही 90 दिनों के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में अपील।

इसे भारतीय क्षेत्र में पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार है फलतः दण्ड देने का अधिकार है और NGT देश में पर्यावरणीय मुद्दों से निपटने के लिये अग्रणी संस्था है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

पर्यावरण शासन में NGT की भूमिका

- जल प्रदूषण के लिये कार्यवाही
  - जल प्रदूषण अधिनियम 1974
- वायु प्रदूषण के लिये
  - वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 के तहत
- वन संरक्षण अधिनियम 1980
  - इसके तहत NGT को अधिकार
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत कार्यवाही
- नदी संरक्षण के लिये कार्यवाही किया गया
- 'मास्टर टैंक' कोर्ट की तरह कार्यवाही
- भारत के UNFCCC से संबंधित Paris समझौते के सहयोग
- नेट जीरो उत्सर्जन में सहयोग
- सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में सहयोगी

निष्कर्षतः कहा जा सकता है राष्ट्रीय हरित अधिकरण पर्यावरण मुद्दों पर भारत की एक महत्त्वपूर्ण संस्था है जो अपने कार्यों से प्राकृतिक न्याय को सुनिश्चित कर रही है

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

5. भारत में न्यायिक सक्रियता का महत्त्वपूर्ण योगदान एक सुरक्षा वाल्व तथा यह विश्वास प्रदान करना है कि न्याय पहुँच से परे नहीं है। कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द) 10

The great contribution of Judicial activism in India has been to provide a safety valve and a hope that justice is not beyond reach. Critically analyze the statement. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

भारतीय न्यायिक इतिहास में यह संकल्पना 1980 के दशक में सामने आयी और इसके प्रवर्तक जस्टिस भगवती को माना जाता है।

न्यायिक सक्रियता के लाभ

- (लोकहित याचिका) PIL के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय
- वादी - प्रतिवादी प्रक्रिया को नजरअंदाज
- गरीबों को न्याय तक पहुँच
- संवेदनशील वर्गों को सामाजिक कल्याण की मुख्य धारा में लाया गया
- जो लोग न्यायालय नहीं आ सकते उनके अधिकारों का संरक्षण
- तीसरे पक्ष द्वारा समूहों के अधिकारों को बढ़ावा
- वास्तविक लोक कल्याण की अवधारणा
- पूर्ण न्याय की अवधारणा मजबूत

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

साक्रियता से नुकसान

- विधायिका एवं कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप
  - दिल्ली में सीलिंग
  - हाईवे पर शराब प्रतिबंध
- संवैधानिक नियमों का उल्लंघन
- शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कमजोर
- संघवाद की प्रक्रिया कमजोर
- विशेषज्ञता के अभाव के कारण आर्थिक नुकसान हुआ सरकार को
  - 2G आवंटन के मामले में

निष्कर्षतः कहा जा सकता है क्योंकि न्यायिक सक्रियता ने पूर्ण न्याय अनुच्छेद 142 की अवधारणा को लागू किया और जीवन के अधिकार को जमीनी स्तर पर ~~[illegible]~~ लागू किया एवं भारतीय समाज का समावेशी विकास किया।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti दृष्टि The Vision

6. चुनावों के राज्य वित्तपोषण की अवधारणा से आप किस सीमा तक सहमत हैं? (150 शब्द) 10

To what extent do you agree with the concept of state financing of elections? (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

इंद्रजीत गुप्ता समिति एवं 2nd ARC की रिपोर्ट ने चुनावों के राज्य वित्तपोषण की अवधारणा को जन्म दिया।

लाभ

- राजनीतिक दलों द्वारा मनी लाउंड्रिंग जैसे केसों में कमी
- फंड्स जैसी अवधारणाओं में कमी
- विशेषज्ञ व्यक्ति राजनीति में आ सकता है
- भाई भतीजावाद को रोका जा सकता है
- राजनीतिक इच्छाशक्ति वाला व्यक्ति सरकार में
- अत्यधिक खर्च प्रवृत्ति पर रोक
- भ्रष्टाचार पर रोक

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

चुनौतियाँ

- → भाई-भतीजावाद की एक नई अवधारणा का जन्म हो सकता है
- → उद्देश्य का सही मार्ग न मिल पाये
- → राजनीतिक दल अलग से खर्चा कर सकते हैं
- → सत्तारूढ़ पार्टी प्रभावी हो सकती है
- → विपक्ष को खत्म कर सकती है
- → लोकतांत्रिक मूल्यों का अवमूल्यन

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि राज्य वित्तपोषण की अवधारणा का उपयोग प्रारंभिक रूप से किसी राज्य की विधानसभा में प्रायोगिक रूप में किया जा सकता है तत्पश्चात् उसका मूल्यांकन कर उसे आगे बढ़ाने पर बल दिया जा सकता है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti दृष्टि The Vision

7. सामाजिक अंकेक्षण, जवाबदेहिता को लागू करने और प्रशासन में पारदर्शिता लाने का एक महत्त्वपूर्ण तंत्र है। भारत में सामाजिक अंकेक्षण के लिये उपलब्ध विभिन्न विधायी समर्थनों पर प्रकाश डालिये। (150 शब्द) 10

Social Audit is an important mechanism to enforce accountability and provide transparency in the administration. Highlight various legislative supports available for social audit in India. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

सामाजिक अंकेक्षण से तात्पर्य है किसी कार्य का भविष्य में समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इसे किस रूप में बेहतर तरीके से लागू किया जाये।

सामाजिक अंकेक्षण के लाभ

- → जवाबदेहिता सुनिश्चित होगी
  - ↳ वस्तुतः कंपनी, सरकारों को कार्यों के प्रति जवाबदेह बनाया जा सकता है
  - ↳ जैसे सिंगल प्लास्टिक का उत्तरदायित्व निर्माणकर्ता के ऊपर डाला गया
- → प्रशासन में पारदर्शिता
  - → वस्तुतः सामाजिक आदि

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

के माध्यम से प्रशासन में किसी कार्य
को पारदर्शी बनाया जा सकता है
और वस्तु एवं कार्य के गुण और
प्रावधान को पब्लिक डोमेन में
रखा जा सकता है
जैसे CSR के माध्यम से
कंपनी अपना लाभ का 2% योगदान
देती हैं।
- पर्यावरण प्रभाव को स्पष्ट करने
के लिये पहले पर्यावरण मंजूरी
लेना

निष्कर्षतः सामाजिक ऑडिट के
माध्यम से न सिर्फ पारदर्शिता
एवं जवाबदेही सुनिश्चित होगी बल्कि
नागरिक अधिकारों को भी
क्रियान्वित किया जा सकेगा।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

8. प्रस्तावित बहु-राज्य सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2022 भारत में सहकारी समितियों के संचालन में सुधार का उद्देश्य रखता है। इस संशोधन के महत्त्व पर बल देते हुए इसके प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

The proposed multi-state cooperative societies (Amendment) Bill 2022 seeks to revamp the operation of cooperative societies in India. Discuss the key provisions of the Bill, emphasizing the importance of this amendment. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

सहकारी समिति भारतीय संविधान
में सातवीं अनुसूची के राज्य
का विषय है।

वस्तुतः सहकारी समिति
का उल्लेख अनुच्छेद 19 एवं
अनुच्छेद 43 के उल्लेखित है

तो वहीं बहु राज्य सहकारी
समिति (संशोधन) बिल, 2022 में
केंद्र सरकार द्वारा विनियम किया
जायेगा अर्थात केंद्र का
नियंत्रण सुनिश्चित होगा साथ
ही इन के लिये नियम कानून
भी केंद्र द्वारा लागू होगा

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

महत्व → जवाबदेही सुनिश्चित

→ सहकारी समितियों पर नियंत्रण

→ विनियम

→ पारदर्शी

→ भ्रष्टाचार पर नियंत्रण

प्रावधान

→ राज्य के नियंत्रण एवं विनियम के दायरा केंद्र के अधीन

→ राज्य की अपनी निधि राज्य सहकारी समिति को लेना रहेगी

→ केंद्र द्वारा निदेशकों की नियुक्ति के लिये निर्देश

→ कार्यों को सार्वजनिक करना

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

9. 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये, जो जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। (150 शब्द) 10

Critically evaluate the 73rd Constitutional Amendment Act 1992, that seeks to establish democracy at the grassroots. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

73वें संविधान संशोधन Act, 1992 के तहत स्थानीय शासन के अंतर्गत नगरपालिका को स्थापित किया गया। अनुच्छेद अनुच्छेद (0-ZA)

नगरपालिका को 18 विषय सौंपे गये जबकि यह इनको लागू कर लोकतंत्र की स्थापना पर बल देगा।

लोकतंत्र की स्थापना में नगरपालिका की भूमिका

→ बल विकास प्रणाली

→ सहभागी लोकतंत्र
- → जनपद विकास समिति
- → महानगर नियोजन समिति

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

- नीति निर्माण पर बल
- पीने के पानी की उपलब्धता
- उद्यान
- स्वास्थ्य सुरक्षा पर बल
- सड़कें निर्माण
- बिजली को कल्याणकारी बढ़ावा
- आर्थिक सहभागिता
- वार्ड समितियों के माध्यम से विकास

निष्कर्षतः कहा जा सकता है नगरपालिका राज्य वित्त आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से स्थानीय विकास को बढ़ावा देता है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

10. जनगणना में होने वाली देरी से विकासात्मक पहलों की प्रभावशीलता और दक्षता प्रभावित होने की संभावना बनी रहती है। चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

Delay in Population census has the potential to affect the efficacy and efficiency of developmental initiatives. Discuss. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

जनगणना किसी राष्ट्र की वास्तविक छवि प्रस्तुत करता है और इस माध्यम से सरकार अपनी नीति निर्माण लागू करने में आसानी होती और 'कल्याणकारी राज्य की अवधारणा' को बढ़ावा मिलता है।

जनगणना के होने वाली देरी से होने वाले प्रभाव

- योजनाओं का उचित क्रियान्वयन नहीं हो पाता
- बजट का निर्माण सही रूप पूर्ण तरीके से नहीं
- नागरिक विकास पर चोट

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

→ प्रादेशिक असंतुलन

→ क्षेत्रीय अस्थिरता

→ स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव

→ पैरामीटर प्रभावित होते हैं

→ जनसंख्या का सही स्वरूप सामने नहीं आता

→ कार्यबल सही रूप से सामने नहीं

→ महिलाओं की सहभागिता सही नहीं

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि जनगणना किसी राष्ट्र की वास्तविक छवि प्रस्तुत करती है अतः उसी के अनुसार ही सरकार अपने कार्यों पर चलती है इसलिए देरी से जनगणना स्वयं प्रगति नहीं है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

11. बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य के आलोक में भारत-जापान सामरिक संबंधों में सहयोग के उभरते क्षेत्र और चुनौतियाँ क्या हैं? (250 शब्द) 15

In light of the changing geopolitical landscape, what are the emerging areas of cooperation and potential challenges in the India-Japan strategic relationship? (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

भारत एवं जापान के बीच स्वतंत्रता पूर्व से ही संबंध रहे हैं जहाँ वे ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे तो वहीं वर्तमान में भारत और जापान के बीच राजनीतिक, आर्थिक, मित्रतापूर्ण संबंध निर्मित हुये हैं।

भारत-जापान के सहयोग उभरते हुये क्षेत्र

→ आर्थिक
  → जापानी संबंधों में मजबूती
  → भारत को कम ब्याज पर ऋण

→ वैज्ञानिक तकनीकी
  → जापान द्वारा बुलेट ट्रेन का भारत में विकास

→ सांस्कृतिक एवं धार्मिक
  → भारत के बौद्ध धर्म स्थलों की प्रधानता
  फलतः भारत जापानियों के लिये पर्यटन का केन्द्र

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

→ QUAD
  - क्वाड समूहों में सहभागिता साझा हित

→ CEPA भारत-जापान के बीच

→ हिंद-प्रशांत क्षेत्र के दोनों ही देश शांति स्थापना पर बल देते हैं

→ हाल ही में गुजरात में आये चक्रवात विपत्तियों के लिये जापान जैसे वैज्ञानिक तकनीकी देश से सहयोग लिया जा सकता है

→ UNSC की स्थायी सदस्यता में सहभागिता का समर्थन

→ चुनौतियाँ
  - जापान में श्रम बल की कमी
  - वैज्ञानिक तकनीकी की क्षेत्र में जापान द्वारा चीन की कंपनियों का विस्तार।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

- शांति पर बल देने के बावजूद हथियारों के आयात प्रदान में संलिप्त नहीं
- जापान बुड्ढों का देश कहा जा रहा है अर्थात भविष्य बाजार शक्ति गिरावट हो सकती है

निष्कर्ष → जापान का प्राकृतिक आपदाओं के प्रति एक लंबा अनुभव है अतः भारत इसका लाभ लिया सकता है एवं भारत में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं से निपटा जा सकता है

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

12. समकालीन वैश्विक व्यवस्था में संयुक्त राष्ट्र के महत्त्व का आकलन कीजिये तथा इसके सुधार और पुनरुद्धार की आवश्यकता पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15

Assess the significance of the United Nations in the contemporary world and discuss the need for its reform and revitalization. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् विश्व की शांति सुरक्षा के लिये 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ जो स्थापना से ही सामाजिक आर्थिक विकास के क्षेत्र में सहभागी रूप एवं सक्रिय भूमिका निभा रहा है।

संयुक्त राष्ट्र का महत्व

- पर्यावरणीय मुद्दों के लिये
  - UNFCCC-1992
  - UNCBD-1992
  - UNCCD-1992
  - Agenda-21-1992
- सामाजिक
  - SDG (17)
  - UNICEF

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

- सांस्कृतिक → UNESCO के माध्यम से
  - world heritage site
  - जियोपार्क
  - पर्यटन एवं कल्चर
- राजनैतिक → सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान
- सुरक्षा
  - UNSC के माध्यम से 1373 नामक निरस्त्रीकरण
  - आतंकवाद के खिलाफ
- स्वास्थ्य
  - विश्व स्वास्थ्य संगठन के माध्यम से चिकित्सा रिपोर्टिंग

UN का सुधार एवं पुनरुद्धार

- स्थायी सदस्यता के लिये — कोफी अन्नान द्वारा (महासचिव)
  - 4-4 देशों की मांग
- इनको नाटो की तरह उपलब्ध करा देनी चाहिये
- विकासशील देशों के हितों

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

से अलग रहते हुये राजनीतिक रूप से स्वतंत्र रहते हुये कार्य करना

→ आत्यायी सदस्यता कें शर्त

→ अल्पविकसित देशों के प्रति जवाबदेही रूप

→ विकसित देशों का पर्यावरणीय संकटों के प्रति अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करना चाहिये

→ नव उपनिवेशवाद के विरुद्ध एक खासा नीति

→ आतंकवाद के खिलाफ एक खासा दृष्टिकोण

~~निष्कर्षतः~~ कहा जा सकता है भारत जैसे अधिक आबादी वाले देश को UNSC के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाये एवं मानव हितों के प्रति रुख किया जाये

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

13. उन कारकों एवं भू-राजनीतिक हितों पर चर्चा कीजिये जो मध्य एशिया के साथ भारत के संबंधों को एक आकार प्रदान करते हैं। उन कदमों का भी उल्लेख कीजिये जिन्हें भारत को इस क्षेत्र में अपनी पहुँच बढ़ाने के लिये उठाने की आवश्यकता है। (250 शब्द) 15

Discuss factors and geopolitical interest which shapes India's engagement with central Asia. Also Mention steps which India need to take to enhance its reach in the region. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

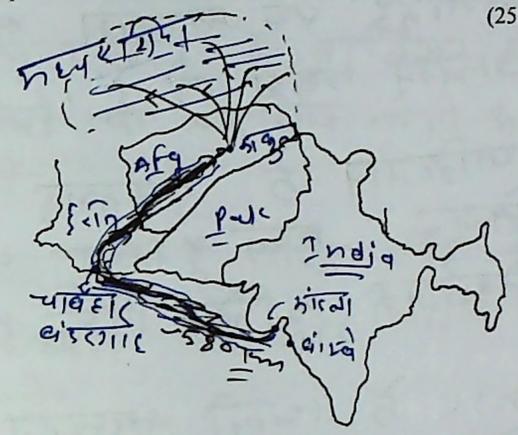

मध्यएशिया रेशम मार्ग पर अवस्थित है जिस पर प्राचीन भारत के आर्थिक घटकों का नियंत्रण था जिनकें उत्थान प्रमुख थे।

भारत एवं मध्यएशिया

→ मध्य एशिया से TAPI पाइपलाइन परियोजना

→ मध्यएशिया गैस एवं यूरेनियम का समृद्ध भंडार है जिसकी भारत में मांग है।

→ भारत की 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स'

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

की नीति को संतुलित करने के लिये

→ समरकंद एवं काशगर से प्राचीन संबंध रहे हैं।

→ पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ मध्य एशिया एक निर्णायक भूमिका निभा सकता है

→ UNSC के स्थायी सदस्यता के लिये सहभागिता

→ SCO में मध्य एशियायी देशों एवं भारत की भागीदारी

→ मध्य एशिया को भारत अपना अंतरिक्ष अनुभव साझा कर सकता है

मध्य एशिया तक पहुँच बढ़ाने के लिये क्या कदम हो सकते हैं?

→ चाबहार बंदरगाह के जरिये अफगानिस्तान एवं स्वतंत्र मध्य एशिया

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

→ द्विपक्षीय व्यापार को मजबूत किया जाये

→ अफगानिस्तान के तालिबान के साथ संबंधों पर एक ठोस नीति अपनायी जाये

→ मध्यएशिया के साथ रूस के संबंधों को और बढ़ाया किया जाये

→ आर्थिक सहायता प्रदान की जाये

→ पर्यावरणीय मंचों का प्रयोग बातचीत
  → UNFCCC
  → UNCBD
  → UNCCD

निष्कर्षतः मध्य एशिया भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं के लिये निर्णायक संबंधी हो सकता है और दोनों मिलकर एशियायी में उदार वातावरण का निर्माण कर सकते हैं

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

14. संविधान निर्माताओं ने भारत के लिये एक समान नागरिक संहिता की "आशा और अपेक्षा" की थी, लेकिन इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया गया है। इस संदर्भ में भारत में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर चर्चा करते हुए इसके कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों का परीक्षण कीजिये। इन चुनौतियों से निपटने के लिये सरकार क्या कदम उठा सकती है? (250 शब्द) 15

The founders of the Constitution had "hoped and expected" a Uniform Civil Code for India but there has been no attempt at framing one. In this regard discuss the need for a Uniform Civil Code in India and examine the challenges in its implementation. What steps can be taken by the government to overcome these challenges? (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारतीय संविधान में समान नागरिक संहिता का उल्लेख भाग-4 में अनुच्छेद-44 में नीति निदेशक सिद्धांतों में किया गया है, जिसका तात्पर्य है कि यह सरकार पर बाध्यकारी नहीं है बल्कि अपेक्षित है।

समान नागरिक की आवश्यकता

- दीवानी अधिकारों के तहत विधिक कानून
- धर्मनिरपेक्षता को कार्यान्वित
- धार्मिक अलगाव की समाप्ति
- शोषण से बचाव → मुस्लिम-बहुविवाह
  - तीन तलाक
  - सती प्रथा
  - पर्दा प्रथा
  - महिलाओं का शोषण

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

- कानूनों की अधिकता से बचाव के लिये
- विधिक नियमों एवं धर्मों के पंजीकरण
- आधुनिक युग में उत्पत्तियों के तहत परिवर्तन आदि
- योजनाओं के क्रियान्वयन में आसानी

चुनौतियाँ

- राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव
- धार्मिक [illegible]
- धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद-25-28)
- जागरूकता का अभाव
- अल्पसंख्यकों को ऐसा लगता है कि यह बहुसंख्यक के हितों में है
- धर्मावलंबियों द्वारा विरोध
- जनता में इच्छाशक्ति का अभाव

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

उपाय — सरकार द्वारा इस रीति से विवाह वालों को पुरस्कृत

- → धार्मिक व्यक्तियों के माध्यम से सकारात्मक विशेषताओं को उद्घाटित करना
- → सद्भाव
- → धर्मों के सामंजस्यपूर्ण
- → शुरुआत से वैकल्पिक रचना
- → गोवा जैसे राज्यों को आदर्श के रूप से प्रचार
- → NGO, सिविल सोसाइटी के जरिये प्रचार
- → जागरूकता कार्यक्रम

निष्कर्षतः कहा जा सकता है: भारतीय समाज विविधताओं वाला है अतः एक झटके में एक बड़ा परिवर्तन उचित नहीं है अतः इसे धीरे-धीरे लागू किया जाना चाहिये और इसके लाभों को उजागर किया जाना चाहिये

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

15. "भारतीय संसद एक संप्रभु विधायिका नहीं है; इसकी शक्तियाँ विशाल हैं लेकिन असीमित नहीं।" कथन पर टिप्पणी कीजिये। (250 शब्द) 15

"The Indian Parliament is not a sovereign legislature; it has vast but not unlimited powers." Comment on the statement. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

भारत में संसदीय शासन है जिसे इंग्लैण्ड से लिया गया है, लेकिन इंग्लैण्ड में संसदीय सर्वोच्च है जबकि भारत में संविधान को सर्वोच्च माना गया है।

भारतीय संसद संपूर्ण भारत क्षेत्र के लिये विधि निर्माण करती है और संविधान में संशोधन के माध्यम से कानून निर्माण पर बल देती है तो वहीं इन कानूनों की समीक्षा न्यायपालिका द्वारा किया जाता है।

दरअसल ब्रिटेन में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान नहीं जबकि भारत में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान है जैसे अनु-13, अनु.-32, अनु-226 आदि।

इसलिये भारतीय संसदीय प्रणाली

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

में ब्रिटेन से कितना न्यारा आती है। तो वहीं इंग्लैण्ड में संविधान जैसी अवधारणा नहीं लेकिन भारत में लिखित संविधान मौजूद है और संसद इसी से शक्ति ग्रहण करती है।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

संसद की शक्तियाँ

- संविधान संशोधन
- आपातकाल का सहमति एवं समाप्ति
- नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन
- CAG, CEC, जैसे पदों को हटाना
- संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष-सदस्यों को हटाना
- बजट निर्माण एवं स्वीकृति
- विधि निर्माण
- लोगों हितों का प्रतिनिधित्व
- धन विधेयक

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

- ~~CE~~, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना आदि

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

संसद की शक्तियों पर सीमाएं आलोचित

- आधारभूत ढांचा
  - केशवानंद भारती वाद (1973)
- विशेष बहुमत
- राज्य सभा की उपस्थिति
- संयुक्त बैठक का प्रावधान
- राष्ट्रपति की उपस्थिति
- न्यायपालिका द्वारा समीक्षा

निष्कर्षतः भारतीय संसद प्रणाली गणतंत्रीय व्यवस्था से संचालित होती है जो लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाये रखते हुये संवैधानिक नियमों के अनुसार संचालित होती है एवं जनाकांक्षाओं के उद्देश्य को निर्धारित करती है

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

16. वैश्वीकरण के युग में, विदेश नीति को आकार देने में पैरा डिप्लोमेसी की अवधारणा का महत्त्व उत्तरोत्तर बढ़ा है और यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उपराष्ट्रीय अभिकर्त्ताओं की बढ़ती भूमिका को प्रदर्शित करता है। भारत के संदर्भ में सविस्तार वर्णन कीजिये। (250 शब्द) 15

"In the era of globalization, the concept of Para diplomacy has become increasingly important in shaping foreign policy, highlighting the growing significance of subnational actors in international relations". Elaborate in the context of India. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

वैश्वीकरण एक ऐसी अवधारणा है जिसके विश्व के देशों के हित एक दूसरे से जुड़े रहते हैं एवं वे एक दूसरे की नीतियों से प्रभावित होते हैं।

विदेश नीति में पैरा डिप्लोमेसी की भूमिका

- सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों स्थापना
- विभिन्न अभिकर्ताओं के माध्यम से संवाद
- विवाद को मीडिया, पत्रकारों के माध्यम से बातचीत
  - जैसे शीत युद्ध के 'हॉट लाइन' कार्यक्रम

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

- ट्रैक-2 डिप्लोमेसी से आगे बढ़ते हुए राज्यों का विदेशी राष्ट्रों से संबंध पर बढ़ावा
- छात्रों एवं चिकित्सकों का आदान प्रदान
- शिक्षकों एवं प्रवासी भारतीयों के माध्यम से संबंधों को मधुर बनाना

उपराष्ट्रीय अभिकर्ताओं की भूमिका

- राज्यों के मुख्यमंत्रियों का विदेशी राष्ट्रों से ~~[illegible]~~ संबंध
- राज्य अपने यहाँ आर्थिक संभावनाओं एवं कारकों के लचीलापन द्वारा
- FDI को आकर्षित कर सकते हैं।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

→ वहीं सीमा विवाद को
को सामाजिक सांस्कृतिक माध्यम
से हल किया जा सकता है

→ जैसे महाराष्ट्र या कर्नाटक
अपने यहां आर्थिक गतिविधियों
के लिये अन्य राज्य की उपस्थिति
स्वीकार करते हैं

→ मध्यप्रदेश का पूर्व एवं पश्चिम
क्षेत्रों से संघर्ष

निष्कर्षतः कहा जा सकता है
भारत के पेरा डिप्लोमेसी एवं
उपराष्ट्रीय अभिकर्ताओं के माध्यम
से भारतीय राज्य विकसित
होने का प्रयास करेंगे, फलतः
आर्थिक विकास एवं व्यक्तिगत
विकास पर सकारात्मक प्रभाव
पड़ेगा।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

17. भारत की राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति के उद्देश्य, लक्ष्यों और महत्त्व पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15
Discuss the objective, goals and significance of India's National Geospatial policy. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

भारत अपनी भू-स्थानिक
नीति के तहत निम्नलिखित
बातों को महत्व देगा है.

आंतरिक उपाय

→ इसके अंतर्गत नक्सलवाद से
निपटने का कार्य

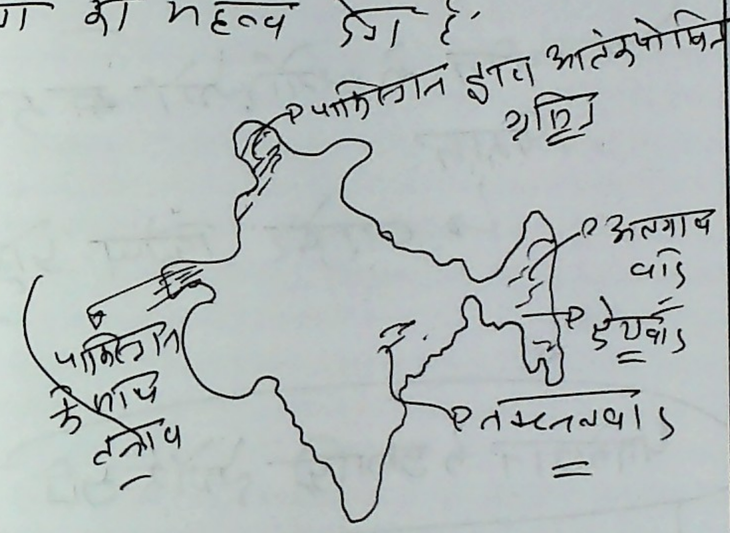

→ अलगाववाद से निपटने पर
बल दिया जाता

→ प्रादेशिक क्षेत्रीय असंतुलन से
उत्पन्न मुद्दों
से निपटा जाता है

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

सीमाओं के संबंध में

- अरुणाचल
  - ↳ वाइब्रेंट प्रोग्राम
- चीन के ~~लोगों~~ गाँवों का विकास
  - ↳ बार्डर विलेज प्रोग्राम

पाकिस्तान के प्रायोजित हमलों के प्रति

- जबकि संबंधों एवं उनके विकास पर बल दिया जाता है
- कठोर नीति एवं जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भारत अपनी भू-स्थानिक स्थिति के विभिन्न दृष्टिकोणों को अपनाता है

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

18. 'गरिमा मानव जीवन का सार है' और यही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) का लक्ष्य है। मानवाधिकारों के संरक्षण में NHRC के प्रदर्शन का मूल्यांकन कीजिये। (250 शब्द) 15

'Dignity is the essence of human life' and it is the objective of NHRC. Evaluate the performance of NHRC in preserving human rights. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने गरिमामय पूर्ण जीवन की अवधारणा को उद्घाटित किया।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का उद्देश्य ही व्यक्ति के अधिकारों के प्रति संवेदनशील रहना और उन्हें व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल देना है तो साथ सम्मान के साथ जीने के उद्देश्य को लागू करना है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्रदर्शन

→ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक वैधानिक आयोग है जिसे भारत में कहीं भी मानव अधिकारों के हनन के खिलाफ शक्तियाँ प्रदान की गई हैं

Copyright - Drishti The Vision Foundation

→ कैदियों के अधिकारों पर बल दिया गया
↳ अजित सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन

→ शक्तिवाहिनी वाद के जीवन साथी चुनने का अधिकार

→ ओलिगा टेलिस वाद के आजीविका का अधिकार

→ शायरा बानो वाद में तीन तलाक का मुद्दा

→ नवतेज सिंह जौहर वाद के समलैंगिकता के मुद्दे को सहमति

→ हुसैनारा खातून बनाम ~~भारत~~ बिहार राज्य में त्वरित सुनवाई एवं वैधानिक सुनवाई का अधिकार

→ MC मेहता वाद में पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दे

→ राम सिंह यादव वाद में आश्रय का अधिकार

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

Copyright - Drishti The Vision Foundation

→ [illegible] काम [illegible] में [illegible] मंदिर में महिलाओं [illegible] कहा जा सकता है [illegible] कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत में मानव के विकास के लिये आवश्यक है और संविधान के आदर्शों अर्थात सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक उपलब्ध कराने के लिये आवश्यक है।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

19. स्वयं सहायता समूह (SHG) देश के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हैं। इन समूहों को प्रोत्साहित करने के लिये सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15

Self Help Groups (SHGs) are the panacea for the socio-economic development of the country. Discuss the steps taken by the government to promote these groups.

(250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

स्वयं सहायता समूह (SHG) भारत में एक दबाव समूह के रूप में उपस्थित हैं जो भारत के संधारणीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

आर्थिक-सामाजिक विकास में स्वयं सहायता समूह की भूमिका

- गरीबों रोजगार प्रदान करना
- स्वास्थ्य अर्थात संस्थागत स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करना
  - संस्थागत प्रसव
  - जननी [illegible] के बारे में
- शिक्षा सहभागिता में भी इन समूहों का योगदान है और पिछड़े क्षेत्रों में विद्यालयों का संचालन
- आर्थिक क्षेत्र में रोजगार सृजन
  - गुजरात-राजस्थान में अमूल मिल्क

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

- सामाजिक क्षेत्र में महिलाओं के हितों के लिये आगे आना तो साथ ही योजना एवं कार्यक्रमों को ग्राम स्तर पर उपलब्ध कराना
- बच्चों के विकास में इनकी भूमिका देखी जा सकती है जैसे- बचपन बचाओ आंदोलन
  - प्रथम फाउंडेशन द्वारा
- बंगाल के कुंडबश्री
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं को साकार
- बाल विवाह पर रोक में इनकी सहभागिता

स्वंय सहायता समूह के लिये सरकारी प्रयास -

- पोषण अभियान
- नाबार्ड द्वारा वित्तपोषित
- मुद्रा योजना (2015) द्वारा वित्तपोषित

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright - Drishti The Vision Foundation

drishti दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

- वात्सल्य योजना का स्वंय सहायता समूहों के माध्यम से क्रियान्वयन
- SEED योजना
- स्वच्छ भारत योजना
- नमस्ते योजना

~~निष्कर्षतः~~ कहा जा सकता है कि स्वंय सहायता समूह सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में सहयोगी रूप में उपस्थित हैं और इनके माध्यम से ग्रामीण - शहरी [illegible] भेद को दूर किया जा सकता है और गांवो का विकास कर शहरीकरण जैसी समस्याओं से निपटा जा सकता है

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright - Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

20. विश्व के लिये ताइवान के सामरिक महत्त्व का आकलन करते हुए यह निर्धारित कीजिये कि एक प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में इसकी अवस्थिति और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में एक संभावित फ्लैशपॉइंट क्षेत्र के रूप में यह 21वीं सदी में शक्ति के भू-राजनीतिक संतुलन को कैसे प्रभावित करता है? (250 शब्द) 15

Assess the strategic significance of Taiwan for the world, and how its position as a major economic power and a potential flashpoint in the Asia-Pacific region affects the geopolitical balance of power in the 21st century. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

चाइना का 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल' नीति के विरुद्ध भारत की 'नेकलेस ऑफ डायमंड' नीति को अपनाना चाहिये और ताइवान से सामरिक संबंधो को बढ़ावा देना चाहिये।

वर्तमान में विश्व में सबसे अधिक सेमीकंडक्टर का उत्पादन ताइवान द्वारा किया जाता है अतः भारत विश्व का सबसे बड़ा बाजार बनने वाला है और सेमीकंडक्टर की मांग भारत में अधिक है

तो वहीं चाइना, ताइवान को अपना भाग मानता है लेकिन ताइवान अपनी विदेश नीति स्वतंत्र रूप से चलाता है फलतः ताइवान के साथ भारत संबंध बनाकर चाइना-पाकिस्तान

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright - Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

संबंधो के खिलाफ नीति बना सकता है

अतः भारत के लिये 21 वीं सदी में भूराजनीतिक संतुलन के लिये ताइवान से संबंध बनाने पर बल देना चाहिये

भारत - ~~संबंध~~ ताइवान के संबंधो का महत्व

- भारत की PLI योजना के लिये आवश्यक
- BRI एवं CPEC परियोजना के खिलाफ
- चाइना डेब्ट ट्रैप नीति का दोनों का विरोध
- साउथ चाइना सी में चाइना के दबाव के ताइवान भारत से संबंधो पर बल देता है
- UNSC में भारत का सहयोगी हो सकता है
- DLI योजना के लिये ताइवान की आवश्यकता

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright - Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

- हिंद प्रशांत महासागर में दोनों के हित समान हैं
- भारत की 'लुक ईस्ट' एवं 'एक्ट ईस्ट' के तहत ताइवान के साथ संबंधों पर बल
- भारत ताइवान को अंतरिक्ष क्षेत्र में मदद कर सकता है
- वैज्ञानिक तकनीकी क्षेत्र में सहयोगी बन सकते हैं

निष्कर्षत: कहा जा सकता है भारत को वर्तमान में यथार्थवादी राजनीति पर जोर देना चाहिये जिसमें राष्ट्रहित सर्वोपरि होते हैं एवं चाइना जब पाकिस्तान के साथ संबंधों पर बल देता है तो भारत को ताइवान के साथ सामरिक हितों पर बल देना चाहिये

Copyright – Drishti The Vision Foundation

Space for Rough Work
(रफ कार्य के लिये स्थान)

Copyright – Drishti The Vision Foundation